

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा,  
देहरादून उत्तराखण्ड।

14 जनवरी, 2011

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

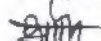
देहरादून, दिनांक: ~~नवम्बर, 2010~~

विषय: शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुमोदित केन्द्रीय सहायतित अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 5-ख (3) 68304/शिक्षक शिक्षा/2010-11 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्र पोषित शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजनान्तर्गत रु0141.025 लाख (रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख दो हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या:1261/xxiv-3/10/02 (16) 2010 दिनांक: 13 सितम्बर, 2010 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रु0 290.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं मानकों एवं मदों के अनुसार किया जायेगा।
2. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
3. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि का किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए उत्तराखण्ड अधि0 प्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुयुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए न छोड़ी जाय।
5. फर्नीचर उपकरण आदि का क्रय शासन के विद्यमान नियमों, आदेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुयुवल का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। उक्त दरें उपलब्ध न होने पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. कम्प्यूटर्स आदि का क्रय अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या:43/xxxiv/115-सू0प्रौ0/06 दिनांक: 07.02.2007 में दिये गये निर्देशों के अनुसार एवं प्रोक्योरमेंट नियमावली एवं उसके क्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में



उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। कय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या:11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय,-आयोजनागत,-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं, 0104-शिक्षक शिक्षा की पुर्नसंरचना एवं पुर्नगठन, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 837(P) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/2010-11 दिनांक: 10 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(मनीषा पंवार)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:1970(1)/XXIV-3/10/04(65)05तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 6- आयुक्त,कुमायूँ मण्डल-नैनीताल/गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।
- 7- अपर शिक्षा निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0,नरेन्द्रनगर/गढ़वाल मण्डल,पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
- 12- वित्त विभाग (अनुभाग-3) उत्तराखण्ड शासन।
- 13- कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
- 14- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)  
अनुसचिव।